



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक ३]

बुधवार, फेब्रुवारी १७, २०१६/माघ २८, शके १९३७

[पृष्ठ ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

राजस्व तथा वन विभाग।

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,  
दिनांकित ५ फरवरी २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2016.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND  
REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३, सन् २०१६।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके  
सन् १९६६ कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन  
का महा. करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;  
४१।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते  
हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभण ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(१)

सन् १९६६ का  
महा. ४१ में एक  
नई धारा २५५ क  
की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे, “उक्त संहिता” कहा गया है) की धारा २५५ सन् १९६६ का महा. ४१।  
की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

“(४) किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष दायर कोई अपील, जिस दिनांक पर ऐसी अपील दायर की गई है उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जायेगी :

परंतु, ऐसी कोई अपील, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ के प्रवृत्त होने के दिनांक से पहले दायर की गई है, तो ऐसे प्रारंभण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी :

परंतु आगे यह कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, किसी अपील का, निपटान करने के लिए अवधि राज्य सरकार या इस निमित्त पदाभिहित कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो इस निमित्त अपीलीय प्राधिकारी का वरिष्ठ है, के द्वारा अधिकतर छह महीनों तक विस्तारित की जा सकेगी ।

(५) यदि अपीलीय प्राधिकारी उप-धारा (४) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अपील का निपटान करने में पर्याप्त कारण के बिना, असफल रहता है, तो वह उस पर लागू होने वाले संबंधित अनुशासनिक नियमों के अनुसरण में अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा।”।

सन् १९६६ का  
महा. ४१ में धारा  
२५७ में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा २५७ की,—

(क) उप-धारा (१) में, निम्नलिखित परंतुक, जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु, इस उप-धारा या उप-धारा (२) के अधीन ऐसी कोई कार्यवाहियाँ अधीनस्थ अधिकारी के निर्णय या आदेश के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा शुरू नहीं की जाएगी।”;

(ख) उप-धारा (३) के,—

(एक) प्रथम परन्तुक के पहले, निम्न परन्तुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

परंतु, किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष लायी गई कोई कार्यवाही जिस दिनांक को ऐसी कार्यवाही दायर की गई है उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी :

परंतु आगे यह कि, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ के प्रवर्तमान होने के दिनांक को किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के सामने, इस धारा के अधीन प्रलंबित कोई कार्यवाही ऐसे प्रारंभण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी :

सन् २०१६  
का महा.  
३।

परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, किसी ऐसी कार्यवाही का निपटान करने की अवधि, राज्य सरकार या इस निमित्त पदाभिहित कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो इस निमित्त पुनरीक्षण प्राधिकरण का वरिष्ठ है, के द्वारा अधिकतर छह महीनों तक विस्तारित की जा सकेगी :

परंतु यह भी कि, यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के बिना, उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई ऐसी कार्यवाहियों का निपटान करने में असफल रहता है, तब वह उस पर लागू होने वाले संबंधित अनुशासनिक नियमों के अनुसरण में अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा ।”;

(दो) प्रथम परन्तुक में, “परन्तु” शब्द के स्थान में, “परन्तु यह भी कि” शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) द्वितीय परन्तुक में, “परन्तु आगे यह कि” शब्दों के स्थान में, “परन्तु यह भी कि ” शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(४) उसमें निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उप-धारा (१) या (२) में जारी किसी आदेश का पुनरीक्षण अनुज्ञेय नहीं होगा ; परंतु उप-धारा (१) या (२) के अधीन ऐसे किसी आदेश का उपांतरण करना, बातिल करना या उलटना केवल राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा ।”।

**वक्तव्य ।**

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि, भूमी के संबंध में न्यायिक-कल्प कार्यवाहियों के स्वरूप में बड़ी संख्या के विवाद शासकीय राजस्व तथा सर्वेक्षण के विभिन्न स्तरों पर प्रलंबित हैं। ऐसे लंबित मामलों, विकास के लिए भूमि की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। यह भी देखा गया है कि, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) की धारा २५७ के अधीन ऐसे विवादों के अंतिम संकल्प लंबीकृत रहते हैं। ऐसे विवादों के संबंध में एक से अधिक पुनरीक्षण संभव हो रहे हैं।

इसलिए, ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निपटान के लिए पुनरीक्षणों की संख्या घटाकर साथ ही साथ समय-सीमा विहित करके उक्त संहिता के सुसंगत उपबंधों का यथोचितरीत्या संशोधित करना इष्टकर समझा गया है जिससे विवादों के पक्षकारों के साथ ही साथ विकास के लिए ऐसी भूमियाँ उपलब्ध करने में समय और पैसे की भी बचत होगी।

२. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित ४ फरवरी २०१६ ।

**चे. विद्यासागर राव,**

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

**मनु कुमार श्रीवास्तव,**

सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

**डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,**

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।